



No. AT/TECH/63/Vol-I

(Through Website)
Dated:18/07/2022

Circular No.227

To

1. The Chief Accountant, RBI Deptt. of Govt. Bank Accounts, Central office C-7, Second Floor, Bandre- Kurla Complex, P B No. 8143, Bandre East Mumbai-400051
2. The Director of Treasuries of all states
3. The Manager CPPC of Public Sector Banks including IDBI
4. The CDA (PD) Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut-250001
5. The CDA-618, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018
6. The Nodal Officers (ICICI/ AXIS/HDFC Bank)....
7. The Pay & Accounts Officers
8. The Post Master Kathua (J&K)
9. All Public Sector Banks
10. Military and Air Attache, Indian Embassy Kathmandu, Nepal.
11. The all DPDOs
12. All Record Offices (Army/Navy/Air Force)
13. Services HQrs. IHQ of MoD (Army/Navy/Air Force)
14. All Head of Offices (Defence Civil Organizations)
15. PCDA(O), Golibar Maidan, Pune
16. SPARSH (Army/Navy/Air Force) O/o the PCDA(Pensions) Prayagraj-211014

Sub: Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner reg.

Ref: Ministry of Personnel, Public, Pension & Pensioners' Welfare letter No. 1/4/2021-P & PW (E) Part-I dated 19/01/2022.

Please find enclosed herewith a copy of Ministry of Personnel, Public, Pension & Pensioners' Welfare, Deptt. of P&PW letter No. 1/4/2021-P & PW (E) Part-I dated 19/01/2022 on the subject.

2. It has been brought to the notice of the ministry that Pension Disbursing Banks are not allowing family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the pensioner or his/her spouse in accordance with Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972 in spite of the fact that such nomination has been duly incorporated in the Pension Payment Order issued to the mentally retarded child. These banks insist for payment of family pension through a guardianship certificate issued by a court of law. Ministry of PP&PW have expressed that it would defeat the purpose of such nomination and would also amount to violation of the statutory provisions of the CCS (pension) rules, 2021.

3. Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972, however provides that in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension can be paid to a person nominated by the Government Servant or the pensioner, as the case may be, and in case, no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. **The Guardianship Certificate issued under Section 14 of the National Trust Act, 1999 (44 of 1999), by a Local Level Committee**, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act. In view of the facts, ministry have directed to follow the said provisions so that undue harassment of such type of family pensioners can be avoided and the purpose of such nomination cannot be defeated and the statutory provisions of the CCS (pension) rules, 2021 cannot be violated also.

4. Ministry of Defence, Department of Ex-Servicemen Welfare, D(Pen/Policy) have also directed to issue similar instructions for Defence pensioners/Family pensioners vide their ID No.2(2)/2022/D(P/) dated 29.03.2022. The provisions contained in Ministry of Personnel, Public, Pension & Pensioners' Welfare, Deptt. of P&PW letter No. 1/4/2021-P & PW (E) Part-I dated 19/01/2022 will apply mutatis mutandis in the case of Defence pensioners/Family pensioners.

5. Therefore, keeping in view the above directions of the ministry, all Pension Disbursing Authorities are requested to take immediate necessary action in all affected cases to avoid undue delay as well as financial hardship to such family pensioners.

sd/-
(Vikas.M.Moharir)
Asstt. Controller (Pensions)

Copy to:-

1. Director, Govt. of India, Min. of PPG&P, :For information
Deptt. of P&APW, 8 Floor, Janpath Bhavan, Janpath, New
Delhi
2. Dy. Secretary, Govt. of India, Min. of Defence, New Delhi :For information
3. Army HQrs, AGs Branch, PAPS4(6), DHQ PO-New Delhi :For information
4. The Defence Accounts Department (DAD) HQrs. :For information
Ulan Batar Road, Palam Delhi Cantt-110 010
5. Officer-in-Charge, Pension Grievance Cell, Ministry of :For information
Defence, New Delhi
6. Secretary. Kendriya Sainik Board, Min. of Defence, West :For information
Block-IV, Wing - V, New Delhi
7. The Pr.CDA (Navy), Cooperage Road Mumbai :For information
8. The Jt. CDA (AF), Subroto Park, New Delhi :For information
9. PCDA(P) Secretariat :For information
10. CDA(P) Secretariat :For information

Page-3

11. All G.Os
12. All OICs of office
13. OIC Gts/Tech
14. Guard file

:For information
For information

For information w.r.t. your letter
No. Gts/Tech/ 05/ LXXXVII dated
26.08.2021



(S.C. Saroj)
Sr. Accounts Officer (Pensions)

सं.1/4/2021-पी & पी डब्ल्यू (ई) भाग-I
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 जनवरी, 2022

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ई-मेल द्वारा)

विषय: सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के बच्चे को, जो किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से निःशक्त है, जिससे वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, कुटुंब पेंशन, कुछ शर्तों के अधीन, आजीवन संदेय है।

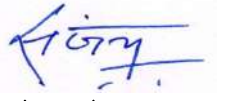
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(iv) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (iii))के अनुसार, ऐसे पुत्र या पुत्री को, जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का संदाय, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो।

3. सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)) में, तथापि यह प्रावधान है कि मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में, कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नाम निर्देशन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो तत्पश्चात यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को, कुटुंब पेंशन संदेय होगी। किसी स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी, उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए संरक्षक के नाम निर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा।

4. इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक रूप से मंद बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में नाम निर्देशन को विधिवत सम्मिलित किया गया है, कुछ मामलों में, पेंशन संवितरण बैंक केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)), के अनुसार पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं। ये बैंक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कुटुंब पेंशन का संदाय करने का आग्रह करते हैं जिसके पास न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाण पत्र हो।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज) में खंड (vii) का उद्देश्य मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात कुटुंब पेंशन का दावा करने में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसका पति/पत्नी मानसिक रूप से मंद बच्चे को संदेय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा ऐसा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया हो, न्यायिक अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा किए गए नाम निर्देशन को मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, यह पेंशन संवितरण बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे को कुटुंब पेंशन संवितरित करें। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए आग्रह करना, ऐसे नाम निर्देशन करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन भी होगा।
7. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके बैंक की सीपीपीसी/पेंशन संदाय शाखाओं को सीसीएस (पेंशन) नियमों के सांविधिक उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की मांग न की जाए। सभी पेंशन संवितरण शाखाओं को भी इन निर्देशों की अभिप्राप्ति की सूचना देने के निर्देश दिए जाएं।
8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(संजय शंकर)

उप सचिव, भारत सरकार

फोन: 24635979

प्रति:

1. लेखा महानियंत्रक
2. केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी
3. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को सूचनार्थ

1/4/2021-पी एंड पी डब्लू (ई) भाग-I
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क - ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक-जनवरी 19, 2022

To

**CMDs of All Pensions Disbursing Banks
(Through E-mail)**

Sub: Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner

I am directed to say that in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules, family pension is payable for life, subject to certain conditions, to a child of a deceased Government servant/pensioner, who is suffering from any disorder or disability of mind or is physically disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years,.

2. As per Rule 50(9)(h)(iv) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (iii) of second proviso to Rule 54(6) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor.

3. Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972), however, provides that in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension can be paid to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. The Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Act,1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act.

4. It has been brought to the notice of this Department that in some cases, the Pension Disbursing Banks are not allowing family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the pensioner or his/her spouse in accordance with Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972) in spite of the fact that such nomination has been duly incorporated in the Pension Payment Order issued to the mentally retarded child. These banks insist for payment of family pension through a person having a guardianship certificate issued by a court of law.

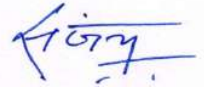
5. Clause (vii) in the Rule 54(9)(h) of the CCS (Pension) Rules, 2021 is intended to avoid any hassles to the child suffering from a mental disability in obtaining the guardianship certificate from the court and in claiming family pension after the death of his/her parents. As per this rule, a Government servant/pensioner or his/her spouse can nominate a person to receive family pension payable to a mentally retarded child. In cases where such nomination is submitted by a Government servant/pensioner/family pensioner, a guardianship certificate issued by a court of law is not necessary.

6. Accordingly, in cases where a nomination made by the Government servant/pensioner/family pensioner has been incorporated in the Pension Payment Order issued to child suffering from a mental disability, it is incumbent on the Pension Disbursing Banks to disburse the family pension in respect such child through the person so nominated. Insisting for a guardianship certificate by the Banks in such cases would defeat the very purpose of such nomination and would also amount to violation of the statutory provisions of the CCS (Pension) Rules, 2021.

7. It is requested that suitable instructions may be issued to the CPPCs/Pension Paying Branches of your Bank for payment of family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner in accordance with the statutory provisions of CCS (Pension) Rules and not to insist for a guardianship certificate issued by a court of law in such cases. All Pension disbursing branches also be asked to acknowledge receipt of these instructions.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय



(संजय शंकर)

भारत सरकार के उप सचिव

टेलीफोन-24635979

Copy to:

1. CGA,
2. CPAO
3. CPPCs of all Pension Disbursing Banks
4. Secretary, Department of Financial Services for information